



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी  
सचिव

Prof. Manish R. Joshi

Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O.No.91-1/2024 (GS)

09 ज्येष्ठ 1947/30<sup>th</sup> May, 2025

Respected Madam/Sir,

As you are aware, the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 was notified on December 9, 2013, to provide a safe and secure environment for women in the workplace.

Sexual harassment results in the violation of the fundamental rights of a woman to equality under Articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution, and the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business, which includes the right to a safe environment free from sexual harassment.

The protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international conventions and instruments such as the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, which was ratified on June 25, 1993, by the Government of India.

The University Grants Commission has also notified the University Grants Commission (Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015, in the Gazette of India, which are available on the UGC website, i.e., [www.ugc.gov.in](http://www.ugc.gov.in). These regulations clearly describe the responsibilities of Higher Educational Institutions (HEIs), grievance redressal mechanisms, the process for making complaints and conducting inquiries, interim redressal, punishment and compensation, consequences of non-compliance, etc.

The UGC Regulations, being statutory in nature, are binding for all HEIs. Specifically, sub-regulation (1) of Regulation 4 of these regulations mandates:

***“... every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment.”***

Cont....

In this regard, the UGC has also repeatedly issued advisories to the HEIs to take the following actions:

- i. To constitute an Internal Complaints Committee (ICC) and a Special/ Women's Cell in the institutions under their administrative control to deal with gender-based violence and conduct gender sensitization programs.
- ii. To display banners and posters at conspicuous places in the buildings to create awareness among employees about sexual harassment and how to prevent it.
- iii. To display the names and contact details of the members of the Internal Complaints Committee on notice boards in the institutions.
- iv. To place a billboard showing the penal consequences of Sexual Harassment. A toll-free number and committed phone numbers should be provided on the billboard.
- v. To display the Women's Helpline Number 181 and Emergency Response Support Number 112 for ease of access to women in distress.
- vi. To upload the following on their respective portals:
  - "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013," and University Grants Commission (Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015.
  - Details regarding the constitution of the Internal Complaints Committee, along with contact information of its members such as name, phone number, address, etc.
- vii. To organize training programmes aimed at raising awareness about sexual harassment for the employees of the institutions.

In view of the above, you are requested to take appropriate action in this regard. It is also requested that the above information may be disseminated to your affiliated colleges as well, and compliance with the same may be ensured.

You are also requested to fill in all details regarding compliance with the above points through online mode on the form available on the SAKSHAM portal i.e. ([saksham.ugc.ac.in](http://saksham.ugc.ac.in)) and the UAMP portal ([uamp.ugc.ac.in](http://uamp.ugc.ac.in)) for the year **2024-2025** at the earliest.

With kind regards,

Yours sincerely,

  
**Manish Joshi**

**The Vice-Chancellors of all Universities.**

**The Principals of all Colleges.**





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी  
सचिव

Prof. Manish R. Joshi

Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

अ.शा.प.सं.91-1/2024 (जीएस)

09 ज्येष्ठ 1947/30<sup>th</sup> मई, 2025

आदरणीय महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को 9 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था।

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और सम्मान के साथ जीने के अधिकार, तथा कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी शामिल है।

यौन उत्पीड़न से संरक्षण और गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और उपकरणों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हैं, जैसे कि महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन (CEDAW), जिसे भारत सरकार ने 25 जून 1993 को अनुमोदित (ratify) किया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भी "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015" को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है, जो UGC की वेबसाइट [www.ugc.gov.in](http://www.ugc.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इन विनियमों में उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) की जिम्मेदारियों, शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत दर्ज करने और जांच की प्रक्रिया, अंतरिम राहत, सजा और मुआवजा, अनुपालन न करने के परिणाम आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है।

यूजीसी विनियम, प्रकृति में वैधानिक होने के कारण, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं। विशेष रूप से, इन विनियमों के विनियमन 4 के उप-विनियम (1) में यह अनिवार्य किया गया है:

**"... प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकरण यौन उत्पीड़न के विरुद्ध लैंगिक संवेदनशीलता के लिए एक अंतर्निहित तंत्र के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करेगा।"**

इस संबंध में, यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को निम्नलिखित कार्रवाई करने के लिए बार-बार सलाह भी जारी की है::

- अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) तथा एक विशेष/महिला प्रकोष्ठ (Special/Women's Cell) का गठन करना, जो लिंग-आधारित हिंसा से संबंधित मामलों का समाधान करें और लैंगिक संवेदनशीलता (gender sensitization) पर कार्यक्रम आयोजित करें।
- संस्थान की इमारतों में प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना, ताकि कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न तथा उससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा सके।

क्रमशः

- iii. संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण प्रदर्शित करना चाहिए।
- iv. यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को दर्शाने वाला एक होर्डिंग लगाना चाहिए और इस होर्डिंग पर एक टोल-फ्री नंबर तथा उससे संबंधित फोन नंबर भी दिए जाने चाहिए।
- v. संकट की स्थिति में महिलाओं की सुविधा हेतु महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता नंबर 112 प्रदर्शित करना चाहिए।
- vi. अपने-अपने पोर्टल्स पर निम्नलिखित जानकारी अपलोड करना:
  - "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013," और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015।
  - आंतरिक शिकायत समिति के गठन के बारे में विवरण, साथ ही इसके सदस्यों की संपर्क जानकारी जैसे नाम, फोन नंबर, पता आदि।
- vii. संस्थानों के कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

उपरोक्त के संदर्भ में, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विषय में उपयुक्त कार्यवाई सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निवेदन है कि उपरोक्त जानकारी आपके अधीनस्थ संबद्ध महाविद्यालयों तक भी प्रसारित की जाए, और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

आपसे यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2024-2025 के लिए उपरोक्त बिंदुओं के अनुपालन से संबंधित सभी विवरण ऑनलाइन मोड के माध्यम से निम्नलिखित पोर्टल्स पर उपलब्ध प्रपत्र में यथाशीघ्र भरें:

- SAKSHAM पोर्टल: [saksham.ugc.ac.in](http://saksham.ugc.ac.in)
- UAMP पोर्टल: [uamp.ugc.ac.in](http://uamp.ugc.ac.in)

इस परामर्शिका का अंग्रेजी संस्करण यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और भाषा संबंधी किसी भी अस्पष्टता के लिए इसका संदर्भ लिया जाना चाहिए।

सादर आभार

भवदीय,



(मनिष जोशी)

प्रतिलिपि:

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य।